भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3587

जिसका उत्तर सोमवार, 04 अगस्त, 2014 को दिया जाना है

एचसीएल के लिए पैकेज

3587. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड (एचसीएल) कंपनी भारी वित्तीय कमी का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एचसीएल को संजीवित रखने के लिए कोई गैर-योजनागत बजटीय सहायता जारी की है;

(ग) क्या सरकार ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी एचसीएल को केबल निर्माण हेतु कुछ क्रयादेश जारी करने का निदेश दिया है; और

(घ) एचसीएल के पुनरूद्धार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री पोन्. राधाकृष्णन)

(क): जी, हां। कंपनी 2003-04 से अत्यधिक वित्तीय कमी का सामना कर रही है।

(ख): जी, हां। मंत्रिमंडल ने दिनांक 27.01.1999 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के लिए वित्तीय पुनर्संरचना, जिसमें नकद हानियों की आंशिक प्रतिपूर्ति के लिए इक्विटी के रूप में ₹75 करोड़ की योजनेतर बजटीय सहायता शामिल की गई थी, के साथ एक सहायता पैकेज अनुमोदित किया है। वर्ष 2003 से वित्तीय कठिनाइयों की वजह से, सरकार प्रत्येक छह माह में एचसीएल के कर्मचारियों को वेतन सहायता देती रही है।

(ग): वर्ष 2003 से सभी इकाइयों में उत्पादन बंद हो गया है और उसके बाद से दूरसंचार विभाग से कोई क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ): आयुध निर्माणी बोर्ड, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिग्रहण के माध्यम से कंपनी का पुनरुद्धार प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

*****